

S-54

Roll No.

LM-102/1002

The Indian Constitution Law : The New Challenges

(भारतीय संवैधानिक विधि : नवीन चुनौतियाँ)

Master of Law (LLM-11/12/16/17)

First Year, Examination, 2018

Time : 3 Hours

Max. Marks : 80

Note : This paper is of **eighty (80)** marks containing **three (03)** Sections A, B and C. Learners are required to attempt the questions contained in these Sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र अस्सी (80) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Section-A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'A' contains four (04) long answer type questions of nineteen (19) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

A-19 P. T. O.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए उन्नीस (19) अंक निर्धारित हैं।
शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने
हैं।

1. Critically examine the widening dimensions of the concept of 'State' in Article 12 of the constitution of India with the help of judicial decisions.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत 'राज्य' की अवधारणा के बढ़ते हुए आयाम का न्यायिक निर्णयों की सहायता से आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

2. Freedom of speech and expression is one of the most cherished fundamental right. Discuss its scope and ambit with reference to the decisions of the Supreme Court.

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अति कुशलता से पोषित अधिकार है। इसके विषय-क्षेत्र एवं सीमा-विस्तार का उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के सन्दर्भ में विवेचन कीजिए।

3. Write an essay on the nexus of politics with crime and business.

अपराध एवं व्यापार जगत् के साथ राजनीति के गठबन्धन पर एक लेख लिखिए।

4. "Public Interest Litigation mechanism has helped the judiciary in spreading its wings to those fields which so far remained untouched." In this reference explain the utility of public interest litigation mechanism with the help of decided cases.

“लोकहित वाद यंत्रावली ने न्यायपालिका को अपने पंखों को उन क्षेत्रों में भी फैलाव में मदद की है, जो अभी तक अछूते थे।” इस संदर्भ में लोकहित वाद यंत्रावली की उपयोगिता की विवेचना निर्णीत वादों की सहायता से कीजिए।

Section-B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section ‘B’ contains eight (08) short answer type questions of eight (08) marks each. Learners are required to answer *four* (04) questions only.

नोट : खण्ड ‘ख’ में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आठ (08) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Explain the provisions as to the administration and control of scheduled areas.

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।

2. Differentiate between ‘Presidential form of Government’ and ‘Parliamentary form of Government.’

‘राष्ट्रपति शासन प्रणाली’ एवं ‘संसदीय शासन प्रणाली’ के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए।

3. State the manner in which a Judge of the Supreme Court is appointed.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, बताइए।

4. Write a note on 'Failure of Constitutional Machinery in a State'.

'राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता' पर एक लेख लिखिए।

5. How does Indian Constitution protect the cultural and educational rights of minorities ? Explain.

भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों को किस प्रकार संरक्षित करता है ? स्पष्ट कीजिए।

6. Write a short note on 'Independence of Judiciary'.

'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

7. Discuss the relationship between 'Fundamental Rights' and 'Directive Principles of State Policy'.

'मौलिक अधिकार' एवं 'राज्य के नीति निर्देशक-तत्त्व' के मध्य सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।

8. Discuss the composition and functions of Election Commission.

चुनाव आयोग के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

Section-C / खण्ड-ग

(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

Note : Section 'C' contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this Section are compulsory.

नोट : खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Fill in the blanks :

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. "Indian Constitution is a federation with strong centralising tendency." This statement is of
"भारतीय संविधान एक केन्द्रीयकृत वाला परिसंघात्मक संविधान है।" यह कथन का है।
2. "Preamble is a part of the Constitution" is the pronouncement of the Supreme Court in the case of
"प्रस्तावना संविधान का एक अंग है।" यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद में अभिनिर्धारित किया गया है।
3. The expression 'Equal Protection of Laws' in Article 14 has been taken from the constitution of
अनुच्छेद 14 में वाक्यांश 'विधियों के समान संरक्षण' को के संविधान से लिया गया है।

4. 'The Directive Principle of State Policy' in Indian Constitution were derived from the constitution of

भारतीय संविधान में 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' को के संविधान से लिया गया है।

5. Part IV-A in the constitution dealing with 'Fundamental Duties' was added by constitution (..... Amendment) Act.

'मूल कर्तव्यों' से सम्बन्धित भाग 4-क संविधान में संविधान (..... संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है।

6. 'The State shall endeavour to promote "international peace and security"' is provided in Article

"राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।" यह अनुच्छेद में उपबन्धित किया गया है।

7. President's Rule in a State under Article 356 of the constitution can remain valid for a maximum period of

संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम की अवधि तक विधिमान्य है।

8. A Judge of the Supreme Court can be removed from his office by a process of impeachment on the ground(s) of

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है।

9. The constitution of India provides for power of judicial review of legislative function under section

भारत का संविधान विधायी कार्यो के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रदान करता है।

10. Clause (.....) of Article of the constitution provides for the composition of Election Commission.

संविधान के अनुच्छेद का वाक्यांश चुनाव आयोग के गठन के सम्बन्ध में प्रावधान करता है।

